

भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
03.07.2019 के
तारांकित प्रश्न सं. 173 का उत्तर

तमिलनाडु में रेल परियोजनाएं

*173. श्री एम. सेल्वराजः
श्री सु. थिरुनवुक्करासरः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पूरे देश में और विशेषकर तमिलनाडु में लंबित और अपूर्ण रेल परियोजनाएं जैसे रेल लाइनों का विद्युतीकरण, छोटी लाइन को बड़ी लाइन में बदलना, रेल ऊपरि पुलों (आर ओ बी) का निर्माण, इत्यादि की कुल संख्या सहित ब्यौरा क्या है;
- (ख) इन परियोजनाओं को सभी प्रकार से कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और
- (ग) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के लिए तमिलनाडु सहित परियोजना और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई?

उत्तर

रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री (श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

तमिलनाडु में रेल परियोजनाओं के संबंध में दिनांक 03.07.2019 को लोक सभा में श्री एम. सेल्वराज और श्री सु. थिरुनवुक्करासर के तारांकित प्रश्न सं.173 के भाग (क) से (ग) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) (i): रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं:

इस समय तमिलनाडु राज्य सहित 34167 करोड़ रु. की लागत वाली 26375 मार्ग किलोमीटर की 70 रेल विद्युतीकरण परियोजनाएं कार्य निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं। आमान परिवर्तन, दोहरीकरण और नई लाइन निर्माण कार्यों के साथ स्वीकृत किए गए कार्यों के अलावा, 2435 मार्ग किलोमीटर के विद्युतीकरण संबंधी कार्य भी निष्पादनाधीन हैं। 01.04.2019 की स्थिति के अनुसार, देश में 55.19 प्रतिशत के बड़ी आमान रेल नेटवर्क को शामिल करते हुए 35448 मार्ग किलोमीटर को विद्युत कर्षण पर चालू कर दिया गया है।

पिछले तीन वर्षों अर्थात् 2016-17 से 2018-19 तथा मौजूदा वर्ष में 01.06.2019 तक 11641 मार्ग किलोमीटर के रेल नेटवर्क को विद्युत कर्षण पर चालू कर दिया गया है, जिसमें तमिलनाडु राज्य में आने वाला 409 मार्ग किलोमीटर का क्षेत्र शामिल है।

(ii): आमान परिवर्तन, नई लाइन और दोहरीकरण परियोजनाएं:

इस समय 189 नई लाइन, 55 आमान परिवर्तन और 247 दोहरीकरण परियोजनाओं सहित 491 रेल परियोजनाएं निष्पादन/योजना/स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 48860.64 कि.मी. है, जिनकी लागत 6.476 लाख करोड़ रु. है, जिसमें से 9113 कि.मी. को चालू कर दिया गया है और मार्च 2019 तक 1.43 लाख करोड़ रु. का व्यय किया गया है। इसमें से तमिलनाडु राज्य में आंशिक या पूर्ण रूप से आने वाली 22 परियोजनाएं (9 नई लाइन, 5 आमान परिवर्तन और 8 दोहरीकरण परियोजनाएं) जिनकी लंबाई 2509 कि.मी. है और लागत 21829 करोड़ रु. है, नियोजन/अनुमोदन/निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

जहां तक देश में आमान परिवर्तन परियोजनाओं का संबंध है, तमिलनाडु राज्य सहित 54,292.53 करोड़ रु. की लागत वाली 7229 किलोमीटर लंबाई की 55 आमान परिवर्तन परियोजनाएं निष्पादन/अनुमोदन/स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से, 3798 कि.मी. को चालू करने में मार्च 2019 तक 19638 करोड़ रु. का व्यय किया गया है। केवल तमिलनाडु राज्य में मार्च 2019 तक 606 कि.मी. लंबाई के आमान परिवर्तन को यातायात के लिए खोल दिया गया है जिस पर 2344 करोड़ रु. का व्यय हुआ है।

(iii) रेल उपरि पुल परियोजनाएं:

पिंक बुक के अनुसार, देशभर में 1581 रेल उपरि पुल के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से, 249 रेल उपरि सड़क पुलों के कार्य पूरे हो गए हैं और यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। शेष पुलों का निर्माण कार्य योजना, अनुमान और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

पिंक बुक के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में 150 रेल उपरि सड़क पुलों के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से, 40 रेल उपरि सड़क पुलों के कार्य पूरे हो गए हैं और यातायात के लिए खोल दिए गए हैं। शेष पुलों का निर्माण कार्य योजना, अनुमान और निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं।

पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (मई तक) के दौरान देशभर में 199 रेल उपरि सड़क पुलों और तमिलनाडु राज्य में 25 रेल उपरि सड़क पुलों के कार्य लागत में भागीदारी के आधार पर पूरे हो गए हैं और यातायात के लिए खोल दिए गए हैं।

(ख): किसी भी रेल परियोजना को समय पर पूरा करना विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है जैसे राज्य सरकार द्वारा शीघ्र भूमि अधिग्रहण, वन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा वन संबंधी मंजूरी, अतिक्रमण उपयोगिताओं (भूमिगत और भूमि पर दोनों) की शिफ्टिंग, विभिन्न प्राधिकरणों से सांविधिक मंजूरी, क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थितियां, परियोजना स्थल पर कानून एवं व्यवस्था, जलवायु संबंधी विचारों के कारण विशेष परियोजना स्थल के लिए वर्ष में काम करने वाले महीनों की संख्या, परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए राज्य सरकार का सहयोग एवं तत्परता, भूकंप, बाढ़, अत्यधिक वर्षा जैसी अप्रत्याशित घटनाएं होना, कामगारों की हड़ताल, माननीय न्यायालयों के आदेश, वर्किंग एजेंसियों/ठेकेदारों आदि की स्थिति एवं परिस्थितियां और इन सभी कारकों से परियोजना की समापन लागत पर प्रभाव पड़ता है, जिसकी समापन स्तर पर अंततः गणना की जाती है।

समग्र राष्ट्र के हित में और लागत में वृद्धि हुए बिना परियोजनाएं समय पर पूरी करना सुनिश्चित करने के लिए रेलवे में विभिन्न स्तरों (फील्ड स्तर, मंडल स्तर एवं बोर्ड स्तर) पर निगरानी की जाती है तथा राज्य सरकारों और संबंधित प्राधिकरणों के पदाधिकारियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं ताकि परियोजनाओं की प्रगति में बाधा डालने वाले लंबित मामलों का समाधान किया जा सके। परियोजनाओं को समय से पहले पूरा करने हेतु सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने ठेकों में बोनस खंड के रूप में ठेकेदारों के लिए प्रोत्साहन अवधारणा अपनाई है, जिससे परियोजनाओं के निष्पादन में और तेजी आएगी।

महत्वपूर्ण परियोजनाओं, क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाओं, अंतिम स्थान संपर्कता परियोजनाओं आदि के लिए मैसर्स भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड से 1.5 लाख करोड़ रु. के ऋण द्वारा संस्थागत वित्तपोषण की व्यवस्था की गई है, जिससे अनिवार्य परियोजनाओं के लिए प्रतिबद्ध निधि व्यवस्था से रेलवे की क्षमता में वृद्धि हुई है।

(ग) रेल विद्युतीकरण परियोजना संबंधी निर्माण कार्य राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की सीमाओं तक सीमित नहीं होते हैं। बहरहाल, पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए आबंटन और व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	आबंटन करोड़ रु. में	व्यय करोड़ रु. में
2016-17	3396.00	2955.89
2017-18	3456.96	3837.08
2018-19	6302.00	7028.50
2019-20	6960.26	1113.88 (मई 2019 तक)

पिछले तीन वर्षों और मौजूदा वर्ष के दौरान आरओबी/आरयूबी के निर्माण पर आबंटन और व्यय का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नानुसार है:

वर्ष	आबंटन करोड़ रु. में	व्यय करोड़ रु. में
2016-17	3066.17	3170.55
2017-18	4000.00	3174.30
2018-19	4203.18	3543.45
2019-20	4100.00	639.96 (मई 2019 तक)

आमान परिवर्तन परियोजनाओं पर व्यय की गई निधि, निधि के आबंटन एवं व्यय का ब्यौरा भारतीय रेल की वेबसाइट अर्थात (www.indianrailways.gov.in) पर लिंक http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/view_section_new.jsp?lang=0&id=0_1,304,366,539,2148 के अंतर्गत उपलब्ध है और साथ ही यह ब्यौरा संसद के समक्ष प्रस्तुत किए गए प्रत्येक वर्ष के बजट में पिक बुक में भी उपलब्ध होता है।
